Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
April 2024 5(4), 2362– 2365

DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY IN INDIA AND ITS SOCIO-ECONOMIC IMPACT

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

Dr. Savitaben H. Desai [1]

[1] Department of Economics, (HOD) Idar Anjana Patidar H. K. M. Arts & P. N. Patel Commerce College, Idar Dist –Sabarkantha (N.G.), India

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i4.2024.6430

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

ABSTRACT

English: The digital economy in India has developed at a rapid pace in the last two decades. Information technology, mobile internet, digitization, e-commerce, and fintech services have not only changed the ways of production and consumption, but also profoundly influenced the social and economic structure. The purpose of this research is to analyze the development of digital economy, its contribution, and socio-economic impacts. Findings show that while digitalization has increased financial inclusion, employment, punishment, and transparency, on the other hand, challenges of digital divide, cyber security, and inequalities have also emerged.

Hindi: भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) पिछले दो दशकों में तीव्र गति से विकसित हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल इंटरनेट, डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स, और फिनटेक सेवाओं ने न केवल उत्पादन और उपभोग के तरीकों को बदला है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढाँचे पर भी गहरा प्रभाव डाला है। इस शोध का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास, इसके योगदान, तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटलाइजेशन ने वित्तीय समावेशन, रोजगार, शिक्षा, और पारदर्शिता में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल विभाजन (Digital Divide), साइबर सुरक्षा और असमानताओं की चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

Keywords: Digital Economy, Economic Development, Social Impact डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रभाव

1. प्रस्तावना

भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा 2015 में शुरू किया गया "डिजिटल इंडिया अभियान" इस परिवर्तन का आधार बना। विश्व बैंक (2022) के अनुसार भारत में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से डिजीटल अर्थव्यवस्था को "ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जो इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचालित होती हैं" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह न केवल GDP वृद्धि दर को प्रभावित करती है बल्कि आय-वितरण, श्रम-बाजार, और उपभोक्ता व्यवहार को भी प्रभावित करती है।

1.1. शोध उद्देश्य

1) भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास का अध्ययन करना।
2) डिजिटलाइजेशन के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
3) डिजिटल अर्थव्यवस्था से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों को पहचानना।

1.2. शोध प्रश्न

1) भारत की GDP वृद्धि में डिजिटल अर्थव्यवस्था का कितना योगदान है?
2) डिजिटल अर्थव्यवस्था ने रोजगार और आय वितरण को किस प्रकार प्रभावित किया है?
3) क्या डिजिटलाइजेशन से सामाजिक समानता बढ़ रही है या असमानता?

2. कार्यप्रणाली

यह शोध द्वितीयक (Secondary Data) पर आधारित है। इसके अंतर्गत RBI, NITI Aayog, विश्व बैंक, IMF, और विभिन्न जर्नल्स तथा शोध-पत्रों से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

2.1. भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास

भारत ने तेज़ी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया है जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, ई-पेमेंट और डिजिटल लेन-देन अब सामान्य व्यवहार बन रहे हैं। "डिजिटल इंडिया" जैसी महत्वाकांक्षी सरकारी योजना ने इस बदलाव को और गति दी है, जिससे वर्चुअल शॉपिंग, ई-कैश, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी एक्सचेंज जैसे शब्द आम हो गए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग रोज़ाना सभी स्तरों—व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों, समुदायों और सरकार—द्वारा निर्णय लेने, उत्पाद बनाने और सेवाएं देने के लिए किया जा रहा है, जिससे सेवाओं की गति और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है (Manoj, 2021) भारतीय सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य देश को एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। इस पहल ने डिजिटल कनेक्टिविटी सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Digital India कार्यक्रम के चलते व्यापक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, और वाणिज्य में डिजिटल तकनीकों की अभूतपूर्व पैठ हुई है जिससे उपभोक्ता व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिला है (Gahlot & Rani, 2024)। डिजिटल भुगतान प्रणालियों (जैसे UPI और मोबाइल वॉलेट्स) के विस्तार और ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी हुई हैं, जिसका सीधा लाभ आर्थिक समावेशन और लेन-देन की दक्षता में मिलता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड की पैठ में 10% वृद्धि से प्रति व्यक्ति जीडीपी में क्रमशः 0.81% और 1.38% की बढ़ोतरी होती है। भारत में डिजिटल इंडिया, आधार और UPI जैसी पहलों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को पुनर्परिभाषित किया है और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाया है (Jadhav, 2025)।

3. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

Digital India पहल ने सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया है। डिजिटल माध्यमों के प्रयोग ने प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को बढ़ाया है, जिससे भारत एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटली सशक्त समाज की ओर अग्रसर हुआ है (Sharma & Sharma, 2021)। इसके साथ ही, डिजिटल तकनीक ने वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को प्रोत्साहित किया है। UPI और Aadhaar-linked services ने आम नागरिक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक भागीदारी में वृद्धि की है। हालाँकि, डिजिटल विभाजन (digital divide) एक गंभीर चुनौती है। भारत में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की असमान पहुँच के कारण समाज में आर्थिक असमानता बनी हुई है। शोध से पता चलता है कि इंटरनेट उपयोग की वृद्धि और डिजिटल कौशल विकास का सीधा सकारात्मक प्रभाव GDP प्रति व्यक्ति और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है (Modi & Lazanyuk, 2025)। इसके अतिरिक्त डिजिटलाइजेशन ने रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर खोले हैं विशेषकर IT और स्टार्टअप क्षेत्र में। लेकिन automation-induced job displacement की समस्या भी सामने आई है जो श्रम बाजार में असमानता पैदा कर सकती है। महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान डिजिटल अपनाने से महिलाओं के व्यवसाय प्रबंधन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है, जिससे परिवार और समुदायों में उनकी भूमिका मजबूत हुई है। यह सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत हैं (Economic Times Report, 2025)

4. नकारात्मक प्रभाव / चुनौतियाँ

डिजिटल विभाजन (Digital divide) — आर्थिक असमानता का बढ़ना

डिजिटल सेवा-पहुँच (इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन, डिजिटल पेमेंट्स) में असमानता ने मौजूदा आय-और अवसर-असमानताओं को और तीक्ष्ण कर दिया है। शोधों और रिपोर्टों के अनुसार भारत में सबसे अमीर 60% लोग गरीब 40% से कई गुना अधिक डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं — जिससे ग्रामीण, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला समूह आर्थिक-विकास के डिजिटल लाभों से वंचित रह जाते हैं। यह विभाजन न केवल उपभोक्ता सुलभता प्रभावित करता है बल्कि रोजगार, शिक्षा और उद्यमिता के अवसरों में दीर्घकालिक अंतर पैदा करता है।

साइबर-सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी (Cybersecurity & financial fraud) — भरोसा और आर्थिक लागत पर असर

डिजिटल लेन-देन के बढ़ते प्रसार के साथ साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल वित्तीय अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। RBI और अन्य रिपोर्टें दर्शाती हैं कि डिजिटल/लोन-फ्रॉड मामलों तथा उच्च-मूल्य धोखाधड़ियों की संख्या और आर्थिक हानि बढ़ी है, जिससे उपभोक्ता-भरोसा घटता है और छोटे राजकोषीय/व्यवसायिक नुकसानों का जोखिम बढ़ता है। ये घटनाएँ वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग-सिस्टम की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ऑटोमेशन और रोज़गार विस्थापन (Automation-induced job displacement) — श्रम बाजार पर दबाव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक ऑटोमेशन और सॉफ्ट-वेयर-ऑटोमेशन से श्रम-गहन सेक्टरों में पारंपरिक नौकरियाँ खतरे में हैं। अध्ययन बताते हैं कि भारत में कुछ क्षेत्रों में उच्च प्रतिशत रोजगार ऑटोमेशन-जोखिम के अधीन हैं; परिणामस्वरूप अस्थायी या दीर्घकालिक बेरोज़गारी, वेतन-दबाव और कौशल-मिसमैच की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं जब तक पुनः-प्रशिक्षण (reskilling) और सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रभावी न हों।

बाजार-एकाग्रता और प्लेटफ़ॉर्म-शक्तियाँ (Market concentration & platform dominance) — छोटे विक्रेता पर प्रभाव

ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटप्लेसों में तेज़ी से बढ़ती बाजार-एकाग्रता (कुछ बड़े प्लेटफ़ॉर्म का वर्चस्व) छोटे खुदरा विक्रेता और पारंपरिक व्यापारियों के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो रही है। प्रतिस्पर्धा-नियमों (competition rules) का उल्लंघन, प्रेफरेंशियल लिस्टिंग और चीफ-डिस्काउंटिंग प्रथाएँ बाजार की स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा को बाधित कर सकती हैं और स्थानीय विक्रेताओं की मार्जिन/बिक्री को कम कर सकती हैं। इससे औद्योगिक ढाँचे में असमानता बढ़ने का खतरा है।

निजता और डेटा-सुरक्षा (Privacy & data protection) — भरोसेमंदता और नैतिक जोखिम

आधार जैसे राष्ट्रीय पहचान प्रणालियों और बड़े-पैमाने पर डेटा-मिलन के कारण व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं। स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा सामाजिक सुरक्षा डेटा के लिंक होने से डेटा-लीक, गलत उपयोग और निजता हनन से सामाजिक व आर्थिक दोनों प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं—विशेषकर संवेदनशील वर्गों के लिए। मजबूत डेटा-प्रोटेक्शन कानून और संस्थागत गारंटी न होने पर ये जोखिम और बढ़ते हैं।

MSMEs/अनौपचारिक क्षेत्रों की वित्तीय पहुँच-सीमाएँ (Credit & inclusion constraints for MSMEs / informal sector)

हालाँकि डिजिटल टूल्स ने कई MSMEs को लाभ पहुँचाया है, पर छोटे कारोबारों के लिये डिजिटल-क्रेडिट-रूपांतरण अभी भी सीमित है—क्रेडिट-स्कोरिंग मॉडल, डिजिटल साक्षरता और ट्रांज़ैक्शन-डेटा की कमी छोटे व्यवसायों की औपचारिक वित्तीय पहुँच रोकती है। इससे आर्थिक पुनरुत्थान और स्थानीय रोजगार सृजन बाधित होता है।

नियामक और अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ (Regulatory & infrastructure gaps)

तेज़ डिजिटल-विस्तार के साथ समुचित नियामक फ्रेमवर्क, उपभोक्ता-सुरक्षा नियम, एवं साइबर कानूनों का अद्यतनीकरण आवश्यक है। साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर—विशेषकर उच्च-गति ब्रॉडबैंड, विश्वसनीय बिजली और स्थानीय आईटी-सपोर्ट—यदि अनुपलब्ध रहे तो डिजिटल बदलाव अस्वीकार या आंशिक रह जाएगा, जिससे निवेश-लागत और क्षेत्रीय असमानताएँ बनी रहेंगी।

5. निष्कर्ष

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने सामाजिक और आर्थिक संरचना दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। डिजिटल इंडिया, आधार, UPI और ब्रॉडबैंड नेटवर्क जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन, सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता और MSMEs की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों के प्रसार से रोज़गार, उद्यमिता और नवप्रवर्तन को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही, डिजिटल उपकरणों और प्लेटफ़ॉर्मों ने लोगों को ज्ञान-आधारित और सशक्त समाज की दिशा में अग्रसर किया है, जिससे सामाजिक भागीदारी और सरकारी कल्याण योजनाओं का प्रभाव भी अधिक प्रभावी हुआ है। यह आर्थिक गतिविधियों की गति और दक्षता को बढ़ाकर GDP और उत्पादन में दीर्घकालिक लाभ देता है। हालाँकि डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ भी स्पष्ट हैं। डिजिटल विभाजन, साइबर धोखाधड़ी, ऑटोमेशन-जनित रोजगार विस्थापन, प्लेटफ़ॉर्म-डोमिनेंस और डेटा सुरक्षा के जोखिम अभी भी भारत के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। इनसे आर्थिक असमानता बढ़ सकती है और सामाजिक भरोसा प्रभावित हो सकता है। इसलिए, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का स्थायी और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति-निर्माताओं को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए:

संदर्भ सूची

Gahlot, B., & Rani, P. (2024). Digitalization in India: Leading the way towards the development. RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary, 9(12), 124–133. https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n12.015

Siddhant Jagdish Jadhav. (2025). The Role of Digital Transformation in Economics Growth: An Indian Perspective. NOLEGEIN- Journal of Entrepreneurship Planning, Development and Management, 8(1).

Manoj, G. (2021). The Digital Economy of India: Challenges and Prospects. Emperor Journal of Economics and Social Science Research, 3(5), 165-170. https://ejessr.mayas.info

Modi, S., & Lazanyuk, I. (2025). A study on impact of digital inequality on economic stability in India. Proceedings of the International Conference on Finance, Economics, Management and IT Business (FEMIB 2024). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/390552005

Sharma, R. L., & Sharma, A. K. (2021). Impact of digitization on social economic transformation of Indian economy. Academy of Marketing Studies Journal, 25(4), 1–7. https://www.abacademies.org/articles/impact-of-digitization-on-social-economic-transformation-of-indian-economy-11259.html

Economic Times Report (2025). 73% MSMEs Report Business Growth via Digital Adoption.